भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 879

गुरूवार, 09 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)

मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत रोजगार

879. **श्रीमती रंजीत रंजनः**

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर, 2022 में 78 लाख भारतीयों की नौकरी चली गई;

(ख) क्या विगत 12 महीनों के दौरान अक्टूबर, 2022 में रोजगार सबसे कम रहा है;

(ग) क्या अक्टूबर, 2022 में वेतनभोगी कर्मचारियों की 2.5 मिलियन नौकरियाँ चली गई है;

(घ) क्या मेक इन इंडिया योजना बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित करने में सक्षम रही है; और

(ङ) यदि हां, तो मेक इन इंडिया योजना की शुरूआत के बाद से सृजित रोजगार का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त होता है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) एवं कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	यूआर (% में)	डब्ल्यूपीआर (% में)
2018-19	5.8	47.3
2019-20	4.8	50.9
2020-21	4.2	52.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़ें, बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जिससे पता चलता है कि लोगों को रोजगार मिलने में वृद्धि हुई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आंकड़े, सामान्य क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कामगारों को कवर करता है। ईपीएफओ अंशदाताओं में शुद्ध वृद्धि, रोजगार सृजन/रोजगार बाजार की सामान्य स्थिति और संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है। ईपीएफ अंशदाता, अक्तूबर 2022 में 11.14 लाख की तुलना में नवम्बर, 2022 के दौरान बढ़कर यह 16.26 लाख हो गए हैं।

'मेक इन इंडिया' पहल, 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, श्रेणी ढांचागत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार में भारत को एक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया में बढ़ावा दिया है। 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्र की योजनाओं का समन्वय करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, कोविड से संबंधित व्यवधानों के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के सकारात्मक समग्र विकास की प्रवृत्ति रही है। इस क्षेत्र में कुल रोजगार वर्ष 2017-18 में 5.7 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में यह 6.24 करोड़ हो गया है।

*****